व्यक्ति, समाज और मर्यादा

साकेत कुमार सहाय

ईमानदारी मात्र एक गुण नहीं, बल्कि स्वस्थ आचरण है। यह परस्पर साहचर्य, विश्वास, प्रेम और प्रगाढ़ता का पर्याय है। व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदार है, तो सहज ही लोग उस पर विश्वास करेंगे। अगर हम अपने जीवन में कोई भी कार्य बेईमानी से करते हैं, तो उसका अपराधबोध जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता।

इसलिए जरूरी है कि हम ईमानदारी को अपनी जीवनशैली का अनिवार्य अंग बनाएं। इसके लिए शुरू से ही परिवार, समाज और संस्थानों को अनुशासित तथा ईमानदार जीवन निर्माण के तत्त्वों की स्थापना के लिए कार्य करना होगा। हम अपने दैनिक जीवन में रोज ही ऐसी घटनाएं देखते हैं, जिनमें काफी लोग अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख होते हैं। कई कर्मचारी अपने कार्यालय में देर से आते हैं, मगर पूछने पर दोष किसी और पर मढ़ते हैं।

छोटे-छोटे आचरण ही हमारे अंदर भ्रष्ट आचार-व्यवहार की नींव डालते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों में प्रारंभ से ही ईमानदार और अनुशासित जीवन जीने का बीज रोपें और उसे सींचे। हमारी शिक्षा-व्यवस्था अपनी जड़ों की ओर लौटे। इसके लिए शिक्षा-व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। वर्तमान मानसिकता एक ज्ञानवान समाज के मुकाबले धनवान समाज को ज्यादा ललचायी नजरों से देखती है, जो हमारे समाज में व्याप्त बेईमानी और अन्य सामाजिक समस्याओं का कारण है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश करे।

आज भ्रष्टाचार हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का हिस्सा-सा बन गया है। बिना इसके किसी काम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें आकंठ डूबा व्यक्ति अपनी गलती आसानी से दूसरे के मत्थे मढ़ देता है या उसके लिए ये सारी बातें ऐसी होती हैं, जैसे दूध में पानी मिला होता है। आज हर विभाग में भ्रष्टाचार दैत्याकार रूप ले चुका है। अब व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके पैसे से होती है। यह पैसा उसने किस प्रकार और कैसे कमाया, यह कोई नहीं देखता। ऐसा इसलिए भी होता है कि ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में यही कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहा, वह इसके प्रयास में है। पद, रसूख के बावजूद जो ईमानदार है, वह बिल्कुल आज के दौर में महात्मा की तरह है। पर दुर्भाग्य यह भी है कि ऐसे लोगों को कई बार परिवार, समाज भी बर्दाश्त नहीं करता। वर्तमान में लोभ-लिप्सा की वजह से भ्रष्ट व्यवस्था शीर्ष पर विराजमान है और यह व्यवस्था देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गई है।

ईमानदार बनने के लिए हमें अपनी उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा, जो हमें चादर से ज्यादा पांव फैलाने को उकसाती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की अहम जरूरत है, पर हमारी ये जरूरतें लगातार बढ़ती जाती हैं और फिर हमारी सारी शक्ति उनकी पूर्ति में लग जाती है। इस तरह इन आवश्यकताओं की पूर्ति में हम खुद एक पैसा कमाने की मशीन बन कर रह जाते हैं। युवाकाल में हमारे रचनात्मकता के स्वप्न धरे के धरे रह जाते हैं। नतीजतन आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में सच्ची निष्ठा और ईमानदारी का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन के प्रत्येक पक्ष के असली मकसद से जुड़ें। असली मकसद ही इंसान को सफलता के पथ पर अग्रसर और उसकी प्रगति को चिर स्थायी बनाता है।

> राष्ट्र, समाज और संगठन के प्रति ईमानदार होना हमारी चरित्र निष्ठा का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। यह सही है कि वर्तमान में हमारे देश में व्याप्त भ्रष्ट परिस्थितियों से कोई भी संतुष्ट नहीं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन हो।

यह अकाट्य सत्य है कि जिंदगी की शुरुआत शून्य से होती है और शून्य पर ही खत्म हो जाती है। अंत में हमारा मूल्यांकन सिर्फ हमारे कर्मों से होता है। उसी के दम पर हम याद किए जाते हैं, न कि पैसों की वजह से। हर इंसान का यह दायित्व बनता है कि वह जब तक जिए, इस संसार में अच्छे कर्म करे, ताकि जब वह इस संसार से विदा हो तो पूरा जग उसके लिए रोए। अच्छे कर्मों की यह सोच हमें सत्य और ईमानदारी की राह की ओर उन्मुख करेगी। इससे हमारे अंदर समाज और राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा उपजेगी।

हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे समाज में सर्वत्र भ्रष्टाचार और असत्य का बोलबाला है। पर, अगर व्यापक रूप में देखें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि समाज में नैतिकता और मर्यादा का तेजी से क्षरण हो रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। समाज में भ्रष्टाचार की उपज एक दिन में नहीं हुई होगी, यह सब कुछ नया भी नहीं है, बल्कि यह सब कम या ज्यादा सदा विद्यमान रही है। पर समाज में चूंकि नैतिकता का स्तर पहले अप्रतिम था तथा अनैतिक कार्यों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। पर समय के साथ यह स्थिति बद से बदतर होती गई। ब्रिटिश गुलामी को भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पर दोषी ठहराने से क्या होगा? देश तो हम सभी का है। इसलिए यह प्रवृत्ति कि यह सब दो सौ वर्षों की गुलाम मानसिकता, सामंतवादी प्रवृत्ति आदि की उपज है।

इसके लिए सबसे अधिक दोषी हमारा समाज, हमारी आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था है। आधुनिक समाज धनिकों को ही योग्य मानती है, चाहे वह धन किसी भी प्रकार से कमाया हुआ हो। शीघ्र धनवान बनने और चमक-दमक को ही तरक्की समझ लेने की मानसिकता ही हमें गलत करने को उकसाती है, जिसका परिणाम है ऐसी स्थिति। जरूरत है इस घाव के रक्त शोधन की।

समाज में ईमानदारी, निष्ठापूर्ण कार्य-व्यवहार की स्थापना के लिए जरूरी है कि भ्रष्ट परिस्थितियों के निर्माण के मूल में काम करने वाली विकृत मनस्थिति में बदलाव लाने की कोशिश की जाए। अन्यथा एक समस्या का उपचार होने से पहले ही दस नई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। हमें इन समस्याओं के समूल विनाश के लिए उनकी जड़ तक जाना और उनके मूल स्रोत को नष्ट करना होगा। इसके लिए पहली आवश्यकता है जनमानस में जड़ें जमाई हुई निकृष्ट स्वार्थपरकता को निरस्त करके चरित्र निष्ठा की उच्च स्तरीय आस्थाओं का प्रतिमान स्थापित किया जाए।

राष्ट्र, समाज और संगठन के प्रति ईमानदार होना हमारी चरित्र निष्ठा का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। यह सही है कि वर्तमान में हमारे देश में व्याप्त भ्रष्ट परिस्थितियों से कोई भी संतुष्ट नहीं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन हो।

सरकारी हो या निजी, दोनों तरह की संस्थाओं में ईमानदारी की व्यवस्था कायम होना बेहद जरूरी है। इसके लिए संवैधानिक तंत्र यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज और व्यवस्था में ईमानदारी तथा पारदर्शिता से सभी कार्य संपन्न हों। इसके साथ यह भी महत्त्वपूर्ण है कि सभी अपने स्तर पर ईमानदारी के सिद्धांत का प्रतिबद्धता से पालन करें। ईमानदार जीवन शैली को अपना कर ही हम एक सशक्त समाज एवं राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे।

नदियों का जीवन

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

जल जीवन मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है 2024 तक हर घर तक पेयजल पहुंचाना। अभी देश के आधे घरों में ही ऐसी सुविधा है। उनमें भी पानी चौबीस घंटे नहीं, औसतन दो घंटे, कभी-कभी तो कुछ मिनट और कुछ स्थानों पर एक दो दिन छोड़ कर पहुंचता है। हालांकि भारतीय मानकों में सुचारु जल आपूर्ति व्यवस्था वह मानी गई है जब प्रति व्यक्ति प्रति दिन चालीस लीटर साफ पेयजल उपलब्ध हो। पर विकास के साथ और विकास के लिए भी पानी की मांग बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की स्वास्थ्य जरूरतों, जैसे साफ-सफाई, खाने-पीने आदि में औसतन करीब पच्चीस लीटर पानी लग जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आवश्यकताओं के साथ पशुओं के लिए पेयजल की जरूरत भी जुड़ी होती है। देश के करीब एक चौथाई क्षेत्रों में, जो अक्सर सूखाग्रस्त रहते हैं, आसपास जल स्रोतों के न होने से इस मानक पर खरे उतर पाना मुश्किल होता है।

फिलहाल हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए अगले पांच सालों में वर्तमान प्रयासों के चौगुने प्रयास करने होंगे। इस बीच दिक्कत यह भी बढ़ती जा रही है कि उपलब्ध जलस्रोत भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। इसलिए जल के शुद्धीकरण में बहुत अधिक समय और धन लग रहा है। पानी को बिना उपचारित किए और सुरक्षित बनाए सीधे घरों में पीने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। पर दुखद यह भी है कि अस्सी प्रतिशत पानी, जो घरों में पहुंचता है, बेकार मान कर बहा दिया जाता है।

अभी भारत में करीब आधी जल आपूर्ति भूमिगत जल से होती है। पर अत्यधिक दोहन और सर्वत्र सतह पर सीमेंट कंकरीट से बनी सड़कों, भवनों आदि के विस्तार से बरसाती पानी के भूजल भंडारों में पहुंचने की राह मुश्किल होती जा रही है। परिणाम स्वरूप खासकर नगरों, महानगरों में भूमिगत जलस्तर बहुत गहराई में पहुंच गया है। साथ ही पास की खेती, उद्योगों या कूड़े-कचरे के भूमिगत जलभंडारों को प्रदूषित भी कर रहे हैं। इस कारण अब चिह्नित हैंडपंपों पर यह चेतावनी देने के लिए निशान भी लगाए जा रहे हैं कि इन हैंडपंपों का पानी पीना घातक हो सकता है। दूसरी तरफ उन प्रसिद्ध विशाल झीलों, तलाबों में भी, जिनसे दशकों से नगरों, महानगरों और राज्यों की राजधानियों को पेयजल आपूर्ति होती रही है, कूड़ा-कचरा, मलमूत्र और प्रदूषण का जमवाड़ा होता जा रहा है। इन झीलों का परिमाप भी कम होता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को पाने के लिए नदियों की क्षमता और संभावनाओं का भी विवेचन हो।

देश में चार सौ से ज्यादा नदियां हैं। राष्ट्रीय नदियों के संरक्षण के लिए एक अलग निदेशालय भी है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, कुछ अरब सागर में। नदियों से निकली नहरें भी कई नगरों-महानगरों में पेयजल आपूर्ति की प्रमुख स्रोत होती हैं। मगर नदियां भी निरंतर नए संकटों में घिरती जा रही हैं। मनुष्य ही इसके लिए मुख्य रूप से दोषी है। अनुपचारित और तथाकथित उपचारित जल-मल, कूड़ा-कचरा और मलबा पहुंचने से नदियों का जल पीने की बात तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं रह गया है। आज नदियां मर रही हैं और मारी भी जा रही हैं।

अगस्त, 2018 में एनजीटी को गंगा के संदर्भ में बताया गया था कि गंगा पर स्थापित सत्तर मॉनीटिरिंग स्टेशनों में से केवल पांच के क्षेत्र में गंगा का पानी पीने और सात में नहाने योग्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।

अपने में प्रचुर जल प्रवाह से कुछ हद तक स्वयं को प्रदूषण मुक्त करने की जो ताकत नदियों को मिलती है, आज वे स्थितियां भी खासकर जलविद्युत्त परियोजनाओं के लिए बने बांधों से खत्म होती जा रही हैं। नदियों और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय असंवेदनशीलता और गिद्ध दृष्टि भारत में ही नहीं है। पूरे विश्व में ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए पृथ्वी और मानव मात्र को बचाने के लिए प्रकृति संरक्षण के उपायों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को जीवित मानव का दर्जा दिए जाने की मुहिम जोर पकड़ रही है।

पूरी दुनिया में नदियों को व्यक्ति के रूप में वैधानिक मान्यता देने का उद्देश्य लोगों को नदियों से उनके व्यवहार में ज्यादा जिम्मेदार बनाना है। इक्वेडर प्रकृति को वे सारे मौलिक अधिकार देता है, जो मनुष्य को हासिल हैं। इसके अंतर्गत प्रकृति को बने रहने, अपने रखरखाव और अपने तथा अपने चक्रों को पुनर्जीवित करने और अपने कार्य करने का अधिकार है। 20 मार्च, 2017 को गंगा, यमुना को जीवित मनुष्य जैसा माने जाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश से भारत को भी दुनिया में विकसित होती इस वैधानिक प्रणाली और वैधानिक सोच में आगे बढ़ने का मौका मिला था, मगर वह फिलहाल इससे चूक गया है। क्योंकि इस आदेश पर केंद्र और राज्य सरकार की आपत्तियों के कारण 7 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश मिल गया था।

संदर्भ

> मानव जीवन के लिए जैसे शरीर में आक्सीजन का होना आवश्यक है, वैसे ही गंगा यमुना या अन्य नदियां भी न मरें, इसके लिए आक्सीजन का उनके पानी में होना आवश्यक है। मगर नदियों में सीवरेज और रासायनिक अपशिष्टों के बहाव से आक्सीजन की कमी से जलचरों की मौत बढ़ती जा रही है।

आदेश में कहा गया था कि नदियां सांस लेती हैं, वे जिंदा हैं। पर्वतों से लेकर सागर तक ये नदियां समुदायों के जीवन को बनाए रखती हैं। भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर लोगों का नदियों से संबंध है, इसलिए भी इनको वैधानिक मानव का दर्जा देकर समाज की आस्था को बचाना है। गंगा दुनिया की पांचवीं सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। गंगा के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने स्वयं नर्मदा नदी को वैधानिक मानव का दर्जा दे दिया था। मानव जीवन के लिए जैसे शरीर में आक्सीजन का होना आवश्यक है, वैसे ही गंगा यमुना या अन्य नदियां भी न मरें, इसके लिए आक्सीजन का उनके पानी में होना आवश्यक है। मगर नदियों में सीवरेज और रासायनिक अपशिष्टों के बहाव से आक्सीजन की कमी से जलचरों की मौत बढ़ती जा रही है।

सबको पेयजल देने के सपने को पूरा करना है, तो नदियों को जिंदा रखने की मुहिम आवश्यक है। प्रदूषित नदियां अपने पार्श्व के भूजल स्रोतों को भी क्षैतजिक रिसाव से प्रदूषित कर सकती हैं। अगर हम नदियों को जीवित व्यक्ति-सा मान लें, तो नदियों को जिंदा रखने के लिए हमारे प्रयास नई ऊर्जा और नए विकल्प पा सकते हैं। नदियां स्वस्थ और जिंदा रहेंगी, तो नदियों में आया पानी देर-सबेर घर में आए पानी का हिस्सा हो जाएगा।

देश में नदियों की सफाई की सोच 1985 में गंगा की सफाई योजना से बनी थी। नदियों को वैधानिक मानने की भी सोच को जमीन देने का काम गंगा के वैधानिक मानव स्तर को वैधानिकता देकर होनी चाहिए। हमें उन्हें केवल हमारी सेवा विकास के लिए संसाधन नहीं माना चाहिए। केंद्र सरकार ने तो अक्तूबर, 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से दिए गए शपथ पत्र से सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2020 तक गंगा प्रदूषण मुक्त कर दी जाएगी। 2020 तो दरवाजे पर ही है।

इस मंदी के दौर में

वित्तमंत्री देर से पहुंचीं एक्सप्रेस अड्डा में पिछले हफ्ते। सो, मुझे फुर्सत मिली वहां आए बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ बातें करने की। बातें शुरू होने से पहले उन्होंने मुझसे आश्वासन मांगा कि उनके नाम नहीं छपेंगे। आवाज धीमी करके उन्होंने कहा, 'माहौल खराब है इसलिए मुंह खोलने से डरते हैं हम।' आश्वासन दिया मैंने तो उन्होंने खुल कर बातें कीं। कहा कि अर्थव्यवस्था पर जो मंदी के बादल छाए हुए हैं पिछले कुछ सालों से, अब और घने हो गए हैं, इसलिए कि जो उम्मीदें उनको मोदी के दूसरे दौर के पहले बजट से थीं, वे पूरी नहीं हुई हैं। 'यही कारण है कि अब भी लोग निवेश करने से कतराते हैं और यही कारण है कि हजारों की तादाद में भारतीय निवेशक देश छोड़ कर भागे हैं। हमने सोचा था कि बजट में कुछ राहत मिलेगी हमें, लेकिन उल्टा हुआ।'

> गरीबी हटाने का एक दूसरा तरीका है, जिसे वे लोग अपनाते हैं जो अपने आप को समाजवादी नहीं मानते हैं। यह तरीका है ऐसा आर्थिक माहौल बनाना, जिसमें निवेशक दौड़े-दौड़े सामने आएं और निवेश इतने बड़े पैमाने पर करने लगें कि करोड़ों नई नौकरियां पैदा होने लग जाएं।

आगे उन्होंने कहा कि उनको खबर है कि बजट भारत सरकर के आला अफसरों ने तैयार करके वित्तमंत्री को दिया। 'इसमें निर्मला सीतारमण का हाथ नहीं था, ऐसा कहा जाता है, इसलिए बजट के बाद उन्होंने कई घोषणाएं की हैं निवेशकों के हौसले बढ़ाने के लिए। शायद इनसे थोड़ा-बहुत फर्क पड़ेगा माहौल में, लेकिन फिलहाल मायूसी फैली हुई है।'

एक्सप्रेस अड्डा एक पांच सितारा होटल के आलीशान, चमकते महलनुमा कमरे में रखा गया था। मैं वहां जल्दी पहुंची थी इस इरादे से कि मंच के पास जगह मिल जाए, ताकि वित्तमंत्री से मैं उस सवाल को पूछ सकूं, जो कई दिनों से पूछना चाहती थी। सवाल वित्तमंत्री के एक बयान से जुड़ा हुआ था। बजट पेश करने के बाद वित्तमंत्री से जब पूछा गया कि उन्होंने 'सुपर-रिच' (अति-अमीर) लोगों पर क्यों एक नया टैक्स लगाया है, जो उनकी मुश्किलें और बढ़ाएगा, तो वित्तमंत्री ने जवाब दिया कि इस सुपर-रिच श्रेणी में सिर्फ पांच हजार लोग आते हैं। इस तरह कही यह बात मंत्रीजी ने जैसे उनको गर्व है कि हमारे इस 'समाजवादी' देश में अमीरों की तादाद इतनी थोड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि उनको इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती है कि सवा सौ करोड़ आबादी वाले इस देश में इतने थोड़े लोग इस श्रेणी में आते हैं। सो, मौका मिलते ही मैंने यह सवाल मंत्रीजी से पूछा। पट जवाब आया- 'मुझे खुशी होगी जब इस श्रेणी में लाखों लोग शामिल होंगे।' एक्सप्रेस अड्डा में मंत्रीजी ने उस दिन स्पष्ट किया कि वे अपने आप को समाजवादी नहीं मानती हैं।

अच्छा लगा इस बात को सुन कर, क्योंकि मोदी के दौर में गलती यही हुई है कि जिन समाजवादी आर्थिक नीतियों ने देश को गरीब रखा है, उनको मोदी ने त्यागने के बदले अपनाया है। इन नीतियों की बुनियाद है गरीबों के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं तैयार करना, जिनमें इतने सूराख होते हैं कि गरीबों तक पहुंचने से पहले आधा पैसा गायब हो जाता हैं। गरीबी हटाने का एक दूसरा तरीका है, जिसे वे लोग अपनाते हैं जो अपने आप को समाजवादी नहीं मानते हैं। यह तरीका है ऐसा आर्थिक माहौल बनाना, जिसमें निवेशक दौड़े-दौड़े सामने आएं और निवेश इतने बड़े पैमाने पर करने लगें कि करोड़ों नई नौकरियां पैदा होने लग जाएं। ऐसा दौर तब देखा हमने जब लाइसेंस राज हटा कर निजी निवेशकों को प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने आमंत्रित किया था, अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए।

देखते-देखते माहौल ऐसा बदला कि कम से कम तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आकर माध्यवर्ग में शामिल हो गए थे। भारतीय निजी कंपनियां इतनी धनी हो गई थीं इस दौर में कि विकसित देशों में निवेश करने लायक हो गई थीं। भारत की छवि बनने लगी थी एक आर्थिक महाशक्ति की। फिर सोनिया गांधी जब आईं तो उन्होंने उन्हीं गरीबी हटाओ आर्थिक नीतियों को अपनाया, जो उनकी सास इंदिरा गांधी की पहचान हुआ करती थीं। सो, मनरेगा जैसी योजनाएं बनने लग गईं, जो रोजगार देने के बदले बेरोजगारी भत्ता देने का काम करने लगीं।

मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने खुल कर मनरेगा की आलोचना की थी लोकसभा के अंदर, लेकिन उसके बाद इस योजना में निवेश कम करने के बदले उन्होंने दुगना कर दिया। वही समाजवादी आर्थिक माहौल बना रहा है। इसको बदलने के लिए वित्तमंत्री को साबित करना होगा अपनी नीतियों से कि उनकी सोच समाजवादी नहीं है।

तू डाल डाल मैं पात पात

जब समाज लंपटाय जाता है तो वही होता है, जो तीस हजारी में हुआ। चैनलों ने जो सीन लाइव दिखाए, वे साफ बताते थे कि जरा-सी बात पर वकीलों और पुलिस में मारा-मारी हो गई। वकील दौड़ा-दौड़ा कर पुलिस कर्मियों को मारते दिखते थे। एक व्यक्ति सीसीटीवी का तार खींचता दिखा। कुछ वकील एक पुलिस अफसर को मारते, धक्का देते दिखे। पुलिस भी 'एक्शन' में दिखी, लेकिन ज्यादातर चैनलों की प्रसारित कहानी में पुलिस पर वकील हावी नजर आए।

दिन भर सब कुछ लाइव आता रहा। सब खबर चैनलों पर एक से सीन रहे। पढ़े-लिखे सभ्रांत लोग आपस में गुंथे दिखते थे! ऐसी गुंडई को देख दर्शक अफसोस और डर महसूस करते थे कि यह क्या हो रहा है? जो हमारी रक्षा के लिए नियुक्त है, वही सरेआम पिट रही है। जब पुलिस असुरक्षित है, तो बाकी की क्या औकात? हम सोचते कि क्या वकील ऐसे ही होते हैं? क्या पुलिस इतनी दयनीय है? क्या आम आदमी का अदालत जाना सुरक्षित है?

चैनलों ने जम के इस तरह की गुंडई की निंदा की। चर्चाओं में रिटायर्ड पुलिस अफसर अफसोस जताते और कहते रहे कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक एंकर कहता रहा कि यह बहुत दिनों की दमित भावना है, जो अचानक बाहर आ गई है।

पुलिस की बेचारगी अगले दिन और साफ हुई, जब दिल्ली पुलिस के अधिकांश सिपाही ड्यूटी छोड़ पुलिस मुख्यालय के सामने बारह घंटे तक न्याय की गुहार लगाते रहे। ये दृश्य अभूतपूर्व किंतु भीषण थे। आइटीओ की सड़कें पुलिस वालों से भरी थीं उनके बीवी बच्चे तक न्याय की मांग की पट्टी लिए नारे लगाते थे। चैनलों में पूरे दिन बार-बार प्रसारित उनकी पिटाई ने उनको अपमानबोध और क्षोभ से भर दिया था। यह इतना अधिक था कि जब पुलिस आयुक्त उनको शांत करने आए। पुलिसवालों ने उन तक को 'हूट' किया। फिर एक के बाद एक कई जूनियर अफसरों ने पुलिसवालों को समझाना चाहा। वे तब भी न माने। उनका कहना था कि जो सबकी रक्षा के लिए हैं, अगर वही असुरक्षित हैं, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? हमारे कई अफसरों को मारा गया, उनको चोटें आईं। पुलिस की गाड़ियां जलाई गईं। उनकी बंदूकें छीनने की कोशिश की गई। वे अपने दो अफसरों के सस्पेन्शन से नाराज थे। उनके बड़े अधिकारी उनको न्याय दिलाने के लिए बड़ी अदालत में अपील नहीं किए, इस पर वे बहुत नाराज थे।

शाम को सारे सीन इंडिया गेट से आए। देर तक वहां भी प्रदर्शन किया, उनकी नाराजी बनी रही। मुश्किल से वे वहां से टले।

इस बीच साकेत कोर्ट के वीडियो ने बहुत कुछ प्रमाणित कर दिया। सीन में आन ड्यूटी, अपनी मोटर साइकिल पर सवार एक पुलिस अफसर की पीठ पर सफेद कमीज पहने एक तगड़े से आदमी ने पहले दो बार कोहनी मारी, फिर गाल पर दो तमाचे मारे, फिर उसे हेलमेट मारा। जवाब में उसने मोटर सइकिल भगा कर अपनी जान बचाई!

तीस हजारी का एक और वीडियो फुटेज दिखा कर एक एंकर ने बताया कि किस तरह कुछ वकील एक महिला पुलिस अधिकारी का कालर खींचते हुए उसे धकियाते दिखे।

प्रतिक्रिया में अगला दिन वकीलों का रहा था। उन्होंने दिल्ली की सभी अदालतों के अंदर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। कैमरों में आकर वकील पुलिस की क्रूरता के बारे में बताते रहे और न्याय की मांग करते रहे।

उसके बाद यह कहानी जांच समिति के हवाले हो गई और खबर खामोश हो गई।

लेकिन तीस हजारी कांड ने एक उपकार किया। दिल्ली की हवा के जहरीलेपन के सूचकांक को व्यवसाय बना देने वाले एनजीओज और एंकरों-रिपोर्टरों की सारी हवा निकाल दी। ऐसा लगा कि उस दिन दिल्ली की हवा शुद्ध हो गई हो। तीस हजारी की कहानी ने हवा की कहानी बजाने ही नहीं दी, लेकिन जैसे ही दिन गुजरा दिल्ली की हवा को अति जहरीला सिद्ध करने वाले आ बैठे। एक चैनल ने हवा में कुल आठ किस्म के जहरीले पदार्थ घुले होने का दावा कर हमारे जैसों को तो एकदम डरा दिया कि अब गए बेटा! मगर ज्यों ही हमने हवा विशेषज्ञों, एंकरों और रिपोर्टरों के स्वस्थ चेहरों को देखा, त्यों ही तसल्ली हुई कि यह सब एनजीओबाजी है। अगर हवा इतनी ही जहरीली होती तो उसे रिपोर्ट करने वाले क्या अब तक रिपोर्ट करने लायक होते?

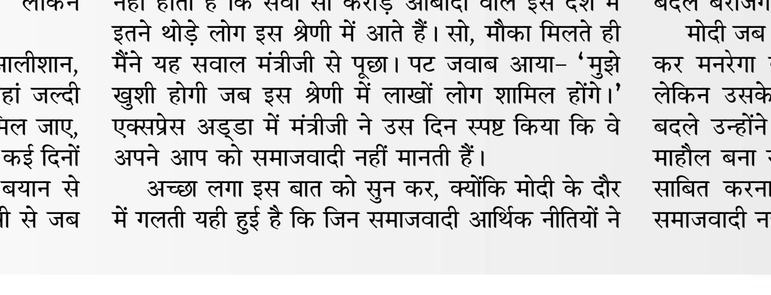

> एक चैनल ने हवा में कुल आठ किस्म के जहरीले पदार्थ घुले होने का दावा कर हमारे जैसों को तो एकदम डरा दिया कि अब गए बेटा! मगर ज्यों ही हमने हवा विशेषज्ञों, एंकरों और रिपोर्टरों के स्वस्थ चेहरों को देखा, त्यों ही तसल्ली हुई कि यह सब एनजीओबाजी है।

यारो! प्रदूषण को राक्षस बना कर 'मास्क' और 'एअर प्यूरीफायर' न बेचो। जो क्रिकेटर कल तक धुंए के खतरे बेचता था, आजकल एअरप्यूरीफायर बेचता नजर आता है। आदरणीय मुफ्त में तो कृपा न कर रहे होंगे!

यह सब कुछ नखरे वाली नाजुक मिजाज मध्यवर्ग की खातिर और उसी के नजरिए से किया जा रहा है। दिल्ली में जो लाखों मजदूर किसान रिक्शेवाले, आटोवाले, झल्लीवाले खोंमचेवाले आदि को रोज कमाना-खाना है, तुम्हारी खतरनाक कहानी में वह कैसे जिंदा है इसकी तो बात करो!

लेकिन इस बार के अभियान ने भक्त और भगवान तक को डरा दिया और वाराणसी के शिवभक्तों ने जहरीली हवा से बचाने के लिए शिवलिंग को भी मास्क पहना दिया! क्यों न पहनाएं! जब नंदी दूध पी सकते हैं, तो भगवान भी जहरीली हवा की चपेट में आ सकते हैं! इसे कहते हैं भक्ति की भक्ति और मजाक का मजाक!

यह सप्ताह महाबली भाजपा की रोज की महाफजीहत देखने में गुजरा। धन्य है शिवसेना कि उसने बिग ब्रदर की सारी अकड़ निकाल दी। संजय राउत रोज सीएम के लिए 'पूर्व निश्चित' फिफ्टी-फिफ्टी की शर्त रखते रहे और रोज भाजपा प्रवक्ता चैनलों के जरिए अपनों को तसल्ली देते रहे कि जल्दी ही फडणवीस की सरकार बन जाएगी!

मगर अभी तक सब कुछ अधर में है! एबीपी ने बताया कि शनिवार तक सरकार बन जानी जरूरी है, वरना राष्ट्रपति शासन लग जाना है!

इस बीच शिवसेना ने अपने विधायकों को पांच सितारा होटल में टिका कर पोचिंग के रास्ते भी बंद कर दिए। तू डाल डाल मैं पात पात इसी को कहते हैं।